आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 08.08.2024 समय : 0705

<><><><><><><><>

- लोकसभा में वित्त विधेयक दो हजार चौबीस पारित– वित्त मंत्री ने कहा– सरकार कर कानूनों को सरल बनाने और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कल डिगलीपुर में एक नए बाल यातायात पार्क का उद्घाटन किया।
- उद्योग निदेशालय पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू कर रहा है।
- संयुक्त विद्युत नियामक आयोग ने द्वीपसमूह में वित्त वर्ष दो हजार चौबीस–पच्चीस के लिए बिजली की दरों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
- भारतीय खेल प्राधिकरण द्वीपसमूह में शारीरिक और खेल संबंधी परीक्षण आयोजित करेगा।

<><><><><><><><>

लोकसभा में कल वित्त विधेयक दो हजार चौबीस पारित हो गया। इसके साथ ही वित्त वर्ष दो हजार चौबीस–पच्चीस के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव प्रभावी हो गए हैं और बजट प्रक्रिया पूरी हो गई है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाने के साथ ही देश में विकास और रोजगार के अवसर बढाना है। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में कर ढांचे में बडे बदलाव किए हैं। उन्होंने बताया कि करों में बढोत्तरी किये बिना सरकार अधिक पारदर्शिता के साथ नियमों के अनुपालन को आसान बनाते हुए एक सरल कराधान व्यवस्था लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सभी करदाताओं की कर देनदारी सैंतीस हजार पांच रुपये कम हो गयी है और इसका मध्यम वर्ग को फायदा होगा।

<><><><><><><><>

पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कल डिगलीपुर में एक नए बाल यातायात पार्क का उद्घाटन किया। युवाओं और बच्चों को यातायात नियमों और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए इस पार्क को डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक ई–लर्निंग कियोस्क "ज्ञान केंद्र" और एक "कल्पोंगकैफे" कैफेटेरिया है, जो इसे बच्चों और परिवारों के लिए एक अनूठा और आकर्षक गंतव्य बनाता है।

यह ट्रैफ़िक पार्क बच्चों को सीखने का माहौल प्रदान करता है जहाँ बच्चे विभिन्न प्रकार के मज़ेदार और रोचक अनुभवों के माध्यम से ट्रैफ़िक नियमों और संकेतों का पता लगा सकते हैं। इस पार्क ब्लैकबोर्ड के साथ एक खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया स्थान और प्रकृति से घिरा एक खुला एम्फीथिएटर है, जो विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों और प्रदर्शनों के लिए एक स्थान प्रदान करता है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ट्रैफिक पार्क एक महत्वपूर्ण सामुदायिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। अंडमान निकोबार पुलिस की यह एक इन–हाउस विकासात्मक परियोजना जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर इस कार्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

<><><><><><><>

उद्योग निदेशालय पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन के नोडल विभाग के रूप में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू कर रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सत्रह सितंबर, दो हजार तेईस को कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं। इस योजना को सूक्ष्म, लघु व मझौले उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अठारह पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया है, जिसमें बढ़ई; नाव निर्माता; कवच निर्माता, मोची; राजमिस्त्री; टोकरी बुनकर; गुड़िया और खिलौना निर्माता; नाई; माला निर्माता; धोबी; दर्जी; और मछली पकड़ने का जाल निर्माता आदि शामिल हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए सभी इच्छुक कारीगरों को किसी भी कार्य दिवस के दौरान आवेदन कर उद्योग निदेशालय या बकुलतला, डिगलीपुर और हट बे में इसके विस्तार कार्यालयों से संपर्क करने के लिए कहा गया है।

<><><><><><><>

संयुक्त विद्युत नियामक आयोग ने द्वीपसमूह में वित्त वर्ष दो हजार चौबीस–पच्चीस के लिए बिजली की दरों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। शून्य से सौ यूनिट तक के लाइफ लाइन कनेक्शन के लिए बिजली की दरें दो रूपये पचास पैसे प्रति किलोवाट आवर निर्धारित की गई है।

घरेलू कनेक्शन के लिए शून्य से सौ यूनिट तक तीन रूपये पच्चीस पैसे, एक सौ एक से दो सौ यूनिट तक छः रूपये पचहत्तर पैसे, दो सौ एक से लेकर पांच सौ यूनिट तक नौ रूपये पचास पैसे तथा पांच सौ एक यूनिट या उससे अधिक के लिए ग्यारह रूपये पचास पैसे प्रति किलोवाट के हिसाब से शुल्क वसूला जाएगा। व्यवसायिक कनेक्शन के लिए शून्य से दो सौ यूनिट तक दस रूपये, दो सौ एक से पांच सौ यूनिट तक बारह रूपये पचहत्तर पैसे, पांच सौ एक से हजार यूनिट तक सोलह रूपये पचहत्तर पैसे और एक हजार यूनिट या उससे अधिक पर अट्ठारह रूपये पचहत्तर पैसे प्रति किलो वाट आवर की दर तय की गई है। इसके अलावा कनेक्शन के हिसाब से निर्धारित शुल्क भी लगेगा। बिजली की नई दरें आयोग और बिजली विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

<><><><><><><>

खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम की परिकल्पना खिलाड़ियों के भीतर से खेल प्रतिभाओं को बाहर निकालना और लोगों में खेल के प्रति चेतना विकसित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य एक ही मंच पर जमीनी स्तर की प्रतिभाओं की पहचान करना है। पिरामिडनुमा प्रतिभा पहचान प्रक्रिया का उद्देश्य फीडर एथलीटों का एक बड़ा समूह तैयार करना है, जो अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रसिद्धि के मार्ग पर चलेंगे। इस संबंध में, भारतीय खेल प्राधिकरण इसी सप्ताह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों जैसे पोर्ट ब्लेयर, रंगत, कदमतला, मायाबंदर और कार निकोबार में शारीरिक परीक्षण और खेल विशिष्ट परीक्षण आयोजित करेगा। इस प्रक्रिया से जुड़े खेल विशिष्ट प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों, स्वयंसेवकों को भारतीय खेल प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार मानदेय दिया जाएगा।

<><><><><><><>

मैसूर में होने वाले सैंतीसवें राष्ट्रीय अंडर–सेवेन चेस चैम्पियनशिप में द्वीपों के चालीस खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चैम्पियनशिप एक सितम्बर से पांच सितम्बर तक चलेगी। सभी चयनित खिलाड़ियों से सहमति पत्र दस तारीख तक व्हाट्सऐप में भेजने या डेरीफार्म स्थित अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन कार्यालय में जमा करने को कहा गया है।

<><><><><><><>

गाराचारामा सब–स्टेशन पर दस एमवीए बिजली ट्रांसफार्मर से जुड़ने वाले जम्पर कनेक्शन का तत्काल रखरखाव किया जाना है। इस कार्य के कारण दस अगस्त को सुबह छह बजे से आठ बजे के बीच एजेंसी हाउस, गाराचारामा, पांच मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र, एकेटी मिनीप्लेक्स, बर्ड लाइन, महावीर नगर, कामराज नगर, बिडनाबाद, रंगाचांग, बरमानल्लाह और चिड़ियाटापु, गराचारामा सब स्टेशन, जापान नाला, ऑस्टिनाबाद, प्रोथ्रापुर, कॉर्बिन कोव, ब्रिचगंज, ब्रुकशाबाद और चक्करगांव के कुछ हिस्सों में आवश्यकतानुसार फीडरवार बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

<><><><><><><>

अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के तहत धन्नीखाड़ी क्षेत्र में छह हजार वर्ग मीटर भूमि, जो जलापूर्ति योजना के लिए आरक्षित थी, जिस पर अतिक्रमण कर सुपारी और नारियल के पेड़ लगाये गये थे उसे नष्ट कर अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। दक्षिण अंडमान ज़िला उपायुक्त ने आम जनता से कहा है कि वे इस तरह की अवैध गतिविधियों से दूर रहे।

<><><><><><><>